



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2009/28 आश्विन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
State of Himachal Pradesh, Shimla

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 15th October, 2009

No. 1-13/2008.—Sanction is hereby accorded to the grant of 18 days earned leave with effect from 21st October 2009 to 7th November, 2009 in favour Shri Anil Kumar Jaswal, Deputy Advocate General of this department with permission to avail suffix Sunday falling on 8th November, 2009.

Certified that Shri Anil Kumar Jaswal, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 18 days earned leave and that this period of leave will count for continuation of his service.

Certified also that the said Anil Kumar Jaswal, Deputy Advocate General, is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where he proceeds on leave.

Sd/-
Advocate General.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 अक्टूबर, 2009

संख्या श्रम (बी) 2-4/2008; ईस्ट (पी.एफ).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, श्री एस0एस0 सैन, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण, धर्मशाला के पक्ष में उनके पत्र संख्या पी0जे0/एल.सी.आई.टी./2925, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के संदर्भ में दिनांक 4-09-2009 से 10-09-2009 तक 7 दिनों का परिवर्तित अवकाश प्रदान करने का सहर्ष आदेश देती हैं।

उपरोक्त अवकाश की समाप्ति पर श्री एस0एस0 सैन, पीठासीन अधिकारी के पक्ष में दिनांक 14-10-2009 तक अवकाश खाते में 289 दिनों का अर्जित अवकाश तथा 17 दिनों का आधे वेतन का अवकाश शेष रहेगा।

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव।

FORESTS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 1st October, 2009*

No. FFE-B-F(5)-4/09.—In continuation of this department notification No.FFE-BC(16)-4/2005, dated 15.5.2006, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate the following persons as Non-Official Members of Governing Council of HP Natural Resource Management Society, through which the H.P. Mid Himalayan watershed Development Project is being implemented in the State:—

- | | |
|---|--|
| 1. Shri Virender Kanwar | Chief Parliamentary Secretary |
| 2. Shri Dile Ram | M.L.A. |
| 3. Smt. Urmil Thakur | M.L.A. |
| 4. Shri Randhir Sharma | M.L.A. |
| 5. Shri Kishori Lal | M.L.A. |
| 6. Dr. Rajiv Saizal | M.L.A. |
| 7. Col. Inder Singh | M.L.A. |
| 8. Mrs. Renu Chadha | M.L.A. |
| 9. Shri Praveen Kumar | M.L.A. |
| 10. Shri Brij Lal | Chairman,
The Kailash Distt.
Coop. Marketing & Consumer Fed., 2
Commercial Bldg. The Mall Shimla. |
| 11. Sh. Baldev Singh Tomar
S/o Sh. Nain Singh Tomar,
VPO Shillai, Distt. Sirmour(HP). | |
| 2. The term of non-official members shall be two years. | |

By Order.
Sd/-
Addl. Chief Secretary.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 16th October, 2009*

No. FDS-B(2)(2)-4/86-I-L.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Pradeep Kumar Pandey, Deputy Controller, Legal Metrology(W&M) to the post of Joint Controller, Legal Metrology(Weights & Measures), Class-I(Gazetted), in the pay scale of Rs.7880-11660, purely on adhoc basis as a stop gap arrangement, in the Weights & Measures Organization of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh.

2. The promotion shall not confer any right upon the Officer for regular promotion, continuation and seniority etc. against the post of Joint Controller, Legal Metrology(W&M). The promotion shall come into effect from the date of joining by the incumbent.

3. The promotion will be subject to O.A. No.19/2008-H.P. Samanya Karamchhari Kalyan Mahasangh versus State of H.P. & ors and other OA's filed in the courts against State of Himachal Pradesh on similar /related subjects.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post the above said officer on promotion as Joint Controller, Legal Metrology(W&M), at Headquarter against vacant post of Joint Controller, Legal Metrology(W&M).

By Order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 16 अक्टूबर, 2009

संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-8/97.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन एवं व्यावृत्तियां.**—(1) अधिसूचना संख्या 1-15/69-एफ एण्ड एस, तारीख 11 दिसम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित दी हिमाचल प्रदेश फूड एण्ड सप्लायज डिपार्टमेंट क्लास-III सर्विस (रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कन्डीशनज ऑफ सर्विस) रूल्स, 1973

का, एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम-2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमाम्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
अनिल खाची
सचिव।

उपाबन्ध —“क”

**हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में , खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी
वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम**

1. पद का नाम.— खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी
2. पदों की संख्या.—17 (सत्रह)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-II, (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—7000-220-8100-275-10300 -340-10980 रुपए।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन पद
6. सीधी भर्ती के लिए आय.—लागू नहीं।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु—लागू नहीं।
- शैक्षिक अर्हताएँ.—लागू नहीं।
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ग्रेड-I/ सांख्यिकी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में लगातार तदर्थ सेवायदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की, उनके अपने-अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम, एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :

- (1) जिला लाहौल एवं स्पिति।
- (2) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
- (3) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- (4) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- (5) कुल्लू जिला का पंद्रह बीस परगना।
- (6) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- (7) जिला किन्नौर।
- (8) जिला सिरमौर में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- (9) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिरुणी, कालीपार मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त

निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात आरंभ और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FDS-A(3)-8/97 Dated, Shimla-171002, the 16.10.09 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th October, 2009

No. FDS- FDS-A(3)-8/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Food and Supplies Officer Class-II, (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Food and Supplies Officer Class-II, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Food & Supplies Department, Class-III, Service (Recruitment, Promotion and Certain conditions of Service) Rules, 1973 notified vide notification No. 1-15/69-F&S, dated 11-12p1973 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these pertain to the post of District Inspectors.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

ANNEXURE-“A”

Recruitment and Promotion Rules for the post of Food & Supplies Officer (Class-II, Non-Gazetted) in the Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh

- 1. Name of the Post.**—Food & Supplies Officer
- 2. Number of Posts.**—17 (seventeen)

3. **Classification.**—Class –II (Non-Gazetted)
4. **Scale of Pay.**—Rs. 7000-220-8100-275-10300-340-10980
5. **Whether Selection Post or non selection post.**—Selection
6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable
7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—Not applicable.
8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s) .**—Age—Not applicable.

Educational Qualifications.—Not applicable

9. **Period of Probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. **Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.**—100% by promotion.

11. **In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.**—By promotion from amongst Inspector, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Grade-I/Statistical Assistant having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(For the purpose of promotion a combined seniority list of all the eligible officials will be prepared on the basis of length of service without disturbing their inter-se seniority in the respective grade).

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the Provisio(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such areas strictly in accordance his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of provision I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of postin in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explation II.—For the purpose of Proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour sub-division of Chamba District.

3. Dodra Kavar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchat Kashapat, Gram Panchats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.
5. Pandra Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Kogra Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangrah, Tach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Teshil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(i) In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, which ever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition?—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 20 अक्टूबर, 2009

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2009.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)-4/2005, तारीख 02-12-2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07-12-2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 46 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 46 के उप नियम (1) में विद्यमान तालिका के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“तालिका

क्रम सं०	भट्टे की क्षमता	प्रवर्ग	प्रतिवर्ष संदेय एकमुश्त रकम जब किसी भट्टे को एक स्थान पर सुलगाने (जलाने) के लिए निर्दिष्ट किया जाता है ।
1.	33 घोड़ियों से अधिक की क्षमता के ईट-भट्टे के लिए	क	2,24,000 /— रुपए जमा 7,800 /— रुपए 33 घोड़ी से उपर की प्रत्येक अतिरिक्त घोड़ी के लिए ।
2.	28 से 33 घोड़ी की संख्या की क्षमता के ईट-भट्टे के लिए	क	2,24,000 /— रुपए
3.	22 से 27 घोड़ी की संख्या की क्षमता के ईट-भट्टे के लिए	ख	1,75,000 /— रुपए
4.	22 से कम घोड़ी की संख्या की क्षमता के ईट-भट्टे के लिए	ग	1,40,000 /— रुपए
5.	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नहीं सुलगाए (जलाया) गए ईट-भट्टे, जिसमें प्रथम अक्टूबर तक भट्टे के अन्दर और बाहर का समस्त प्रवर्गों का स्टॉक पांच लाख ईटों से अधिक का न हो, के लिए	घ	35,000 /— रुपए ”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2009, dated 20-10-2009 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India] .

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th October, 2009

File No. EXN- F(10)-1/2009.—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified vide this department notification No. EXN-F(5)-4/2005, dated 02-12-2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 07-12-2005, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (2nd Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 46.—In sub-rule (1) of rule 46 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 for the existing TABLE, the following shall be substituted, namely:—

“TABLE

Sl. No.	Capacity of Kiln	Category	Lump sum amount payable per annum when a kiln is designated to be fired at one place
1.	Brick-Kiln of capacity of more than 33 number of ghori	A	Rs. 2,24,000/- plus Rs. 7,800/- per additional ghori above 33 Ghori
2.	Brick-kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori	A	Rs. 2,24,000/-
3.	Brick-kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori	B	Rs. 1,75,000/-
4.	Brick-kiln of capacity of below 22 number of Ghori	C	Rs. 1,40,000/-
5.	Brick-kiln not fired during the year ending 30th September in which stock in and outside the kiln as on 1st October last does not exceed five lac bricks of all categories	D	Rs. 35,000/- ”

By order,
Sd/-
Principal Secretary.